

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4348 का उत्तर

तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं में विलंब

4348. श्रीमती कनिमोङ्गी करुणानिधि:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार इस बात से अवगत है कि तमिलनाडु में कई रेल परियोजनाओं, जिनमें पटरियों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और नई रेल लाइनों का निर्माण शामिल है, में अत्यधिक विलंब हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं की स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के कारणों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) मदुरै-थूथुकुडी दोहरीकरण परियोजना जैसी प्रमुख लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण की स्थिति इस प्रकार है:

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए आवश्यक कुल भूमि	4288 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	991 हेक्टेयर (23%)
शेष भूमि जिसका अधिग्रहण किया जाना है	3297 हेक्टेयर (77%)

भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार का सहयोग आवश्यक है।

भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	आवश्यक कुल भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	शेष भूमि जिसका अधिग्रहण किया जाना है (हेक्टेयर में)
1.	टिंडीवनम-तिरुवन्नमलाइ न्यू लाइन (71 कि.मी.)	273	33	240
2.	अट्टीपट्टू - पुत्रूर नई लाइन (88 कि.मी.)	189	0	189
3.	मोरप्पुर - धर्मपुरी (36 कि.मी.)	93	0	93
4.	मन्नारगुडी-पट्टुक्कोट्टई (41 कि.मी.)	152	0	152
5.	तंजावुर-पट्टुक्कोट्टई (52 कि.मी.)	196	0	196

भारत सरकार परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है, बहरहाल सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/कार्यान्वयन राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉर्वर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, ₹33,467 करोड़ की लागत वाली कुल 2,587 किलोमीटर लंबाई की 22 परियोजनाएँ (10 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण), जो पूर्णतः/आंशिक रूप से तमिलनाडु राज्य में आती हैं, योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 665 किलोमीटर को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक ₹7,154 करोड़ का व्यय हो चुका है। सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	10	872	24	1,223
आमान परिवर्तन	3	748	604	3,267
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	9	967	37	2,664
कुल	22	2,587	665	7,154

मदुरै-तूकुडि (तूतीकोरिन) बारास्ता मनियाची दोहरीकरण परियोजना जुलाई 2023 में पूरी हो गई है।

आज की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में स्थित बड़ी लाइन नेटवर्क का लगभग 96% विद्युतीकरण हो चुका है। शेष खंडों में विद्युतीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹879 करोड़/वर्ष
2025-26	₹6,626 करोड़ (7.5 गुना से अधिक)

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी साधनों का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल (स्थलों) के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।
